भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1413 का उत्तर

पर्यटन एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र में रेल सेवा

1413. श्री सतपाल ब्रह्मचारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों को रेल सेवाओं से जोड़ने के लिए कोई परियोजना स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड के गिरिडीह लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और हरियाणा के सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों के लिए इस संबंध में कोई परियोजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

S.K

पर्यटन एवं सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्र में रेल सेवा के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री सतपाल ब्रह्मचारी के अतारांकित प्रश्न सं. 1413 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्य सीमाओं/संसदीय निवार्चन क्षेत्रों के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्वों, पर्यटक संभावना आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पिछले 03 वर्षों के दौरान अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में, देश भर में लगभग 1,44,039 करोड़ रुपये की लागत की कुल 7,697 किलोमीटर लंबाई की 192 परियोजनाओं (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों से भी संपर्क बढ़ाएगी।

झारखंड

झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशत: रूप से पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, और दक्षिण पूर्व रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, गिरिडीह सहित झारखंड राज्य में पड़ने वाली पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 52,885 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,070 किलोमीटर कुल लंबाई की 32 परियोजनाएँ (11 नई लाइनें, 01 अमान परिवर्तन और 20 दोहरीकरण), योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं,

S.K

इनमें से 744 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 15,986 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इसका सार निम्नानुसार है:

श्रेणी	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपये में)
नई लाइन	11	1069	156	3549
आमान परिवर्तन	1	159	90	184
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	20	1842	497	12254
कुल	32	3070	744	15986

इनमें सोन नगर-अंडाल (374 कि.मी.), मधुपुर में बाईपास लाइन (7.40 कि.मी.) और गिरिडीह में पूर्णत:/अंशतः रूप से पड़ने वाली पारसनाथ-मधुबन-गिरिडीह नई लाइन (49 कि.मी.) की मल्टीट्रैकिंग शामिल है।

झारखंड में पूर्णतः/अंशतः रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	457 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	7,302 करोड़ रु. (लगभग 16 गुना)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन की गई नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	287 कि.मी.	57.4 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-24	1,218 कि.मी.	121.8 कि.मी. प्रति वर्ष (2 गुना से अधिक)

हरियाणा

हरियाणा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का लागत,

व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 15,875 करोड़ रुपए की लागत वाली 1,195 कि.मी. कुल लंबाई की 14 रेल परियोजनाएं (05 नई लाइनें और 09 दोहरीकरण), योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं और मार्च, 2024 तक 710 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

हाल ही में, सोनीपत, पानीपत से होकर गुजरने वाली दिल्ली-अंबाला (198 कि.मी.) के बीच तीसरी और चौथी लाइन के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है।

******

S.K